फरीदाबाद
मजदूर समाचार

मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 100 अक्टूबर 1996

अपने बारे में, इस अखबार के बारे में बात करने आप किसी भी दिन मजदूर लाइब्रेरी आ सकते / सकती हैं।

हम चाहते हैं....

★ वह बराबरी जहाँ हर व्यक्ति, प्रत्येक स्त्री व पुरूष अपने-अपने ढँग से खिल सके, महक सके। ★ वह समाज व्यवस्था जिसमें समाज व व्यक्ति के बीच में शत्रुता नहीं हो बल्कि समाज व्यक्ति का सहायक हो। ★ वह माहौल जहाँ बच्चे तनावमुक्त हों। ★ वह स्थिति जिसमें वृद्धों को बुढापे में आदर मिले। ★ वह हालात जिनमें युवाओं की जवानी में रंगत हो। ★ मनुष्यों व प्रकृति के बीच वे रिश्ते जिनमें पर्यावरण जीवन के फलने-फूलने के माफिक हो।

हम जो चाहते हैं उन्हें हासिल करने के लिये, हमारे विचार से, जरूरी है: ऊँच-नीच को खत्म करना; होड को खत्म करना; सीमाओं को खत्म करना; पुलिस खत्म करना; जेलें खत्म करना; अदालतें खत्म करना; प्रतिनिधियों-नुमाइन्दों-लीडरों-बिचौलियों को खत्म करना; मैनेजमेन्टें खत्म करना; मुस्कानें बेचना खत्म करना; स्कूलों को खत्म करना; चूल्हे-चौके की चाकरी के संग-संग दिहाड़ी की गुलामी खत्म करना; मन्डी व मुद्रा को खत्म करना; खुफिया-गोपनीय को खत्म करना;....

● ऊँच-नीच को खत्म करना ताकि हमारे सिर-माथों पर चढे एक के ऊपर दूसरे साहब के बोझ से हम मुक्त हो सकें। ऊँच-नीच वाली व्यवस्थाओं में हमारी मेहनत की उपज के बड़े हिस्से को हमारे ऊपर सवार लोग व उनका तन्त्र खा लेता है और जो बचता है उसका इस्तेमाल हमारे शोषण को बढाने तथा हम पर जकड़ बनाये रखने के वास्ते दमन-तन्त्र को तीखा करने के लिये होता है। ऊँच-नीच के रहते रूखा-सूखा व नीरस जीवन भी हम बहुत मुश्किल से हासिल कर पाते हैं – अक्सर बेवक्त की मौत ही हमारी नियति-सी बन जाती है।

बराबरी वाली समाज व्यवस्था में हमारी मेहनत की उपज हमारे जीवन की तात्कालिक बेहतरी के संग-संग हमें काम के बोझ से आजाद भी करेगी। बराबरी वाले समाज में ज्ञान, कौशल-हुनर और भौतिक-मैटेरियल रूपों में संचित हमारे पूर्वजों की व हमारी मेहनत हमें अधिकाधिक फुर्सत देगी और रुचि व मनमाफिक गतिविधियों के लिये हमें स्वतन्त्रता उपलब्ध करायेगी।

ऊँच-नीच की समाप्ति साहबगिरि को खत्म कर साहबों को भी अपने मन-विवेक को कुचलने की अनिवार्यता से आजाद कर देगी।

● होड़ को खत्म करना ताकि बच्चों का बचपना मिटाने की धारा मोड़ी जा सके। ऊँच-नीच की सीढी पर ऊपर चढने के लिये प्रतियोगिता-दर-प्रतियोगिता में आगे रहने की अनिवार्यता किसी ब्रेकडाउन तक की इजाजत न दे कर हमें मशीन से भी चार कदम आगे ले जा रही है। तन को पूरा तान कर होड़ हमें मन को खींचने को मजबूर करती है। मनुष्यों में कोई भी आज इससे मुक्त नहीं है – सिर-माथों के पिरामिड के शिखर पर बैठे लोग भी होड़ की गिरफ्त में हैं।

फर्स्ट रहने, अव्वल आने की बजाय संग-संग रहने, साथ-साथ चलने में बौना होने का डर नहीं है बल्कि समूह की सामुहिकता की तुलना में विश्व चैम्पियन - नोबेल पुरस्कार विजेता बौने हैं। साँझेपन में, मैल-जोल में, सामुहिकता में सब का बौनापन दूर होता है।

● सीमाओं को खत्म करना ताकि वेतन के लिये मरने व मारने वाले वर्दीधारी मुक्त हो सकें। ऊँच-नीच को बनाये रखने का फौज एक प्रमुख औजार है और फौजों पर हमारी मेहनत की उपज का एक अच्छा-खासा हिस्सा खर्च किया जाता है। देशों और सीमाओं को पवित्र गऊयें प्रस्तुत कर उनकी रक्षा की आड़ में दुनियाँ-भर में हमारे खिलाफ सेना-रूपी मुख्य हथियारबन्द गिरोह संगठित किये गये हैं।

संगीनधारियों के साये में सीमायें हमारे सीधे-सीधे मेल-जोल व तालमेल में बाधा हैं तो देशी-विदेशी के फरेब गुमराह कर हमें आपस में सम्बन्ध स्थापित करने से रोकते हैं।

सीमा शुल्क उर्फ कस्टम ड्युटी नाम वाला बड़ा टैक्स सीमाओं की आड में हमारे ऊपर एक और बोझा है। स्मगलिंग और रिश्वतखोरी में सीमाप्रहरियों, उनके सेनापतियों और कस्टम वालों की हिस्सापत्तियाँ मीठी चटनी की परातें हैं जिनमें छापों के डर इक्की-दुक्की नीम की निमोलियाँ हैं।

सीमाओं और उनके काँटेदार तारों को मिटा कर, देशी-विदेशी दिखाने वाले कँटीले चश्मे उतार कर दुनियाँ-भर में होती इन्सानों की संगतें, मनुष्यों के समागम मानवों के बीच वास्तव में प्यार-मोहब्बत उपजा सकेंगे।

● पुलिस खत्म करना ताकि वर्दी में गुन्डागर्दी करना जिनकी ड्युटी है वे ऐसी नौकरी से मुक्त हो सकें। हमारे विरोधों की व्यापकता व तीव्रता के दृष्टिगत फौजें भी अब छावनियों में छिपे रहने की बजाय तोप गाड़ियों में लद कर दहशत फैलाने हमारी बस्तियों में अक्सर प्रकट हो रही हैं परन्तु फिर भी ऊँच-नीच वाली व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के खिलाफ हमारे रोजाना के विरोधों के दौरान हमारा वास्ता अधिकतर पुलिस से ही पड़ता है। विभिन्न लेबलों वाली पुलिस और खुफिया एजेन्सियों के जाल ऊँच-नीच वाली व्यवस्था के आवश्यक अंग हैं, दमन-शोषण के लिये पुलिस और खुफिया तन्त्र का होना एक लाजमी जरूरत है। प्रचारकों का तो यह काम है परन्तु उनके चक्कर में आ कर जो कोई पुलिस को रक्षक मान लेते हैं वे ही हकीकत से वास्ता पड़ने पर "रक्षक भक्षक हो गये" कहते मिलेंगे। थाने रक्षा के नहीं बल्कि यातना के केन्द्र हैं। मुखबिरों-दलालों-अपराधियों की मुखिया होती है पुलिस। दिल खोल कर बात करते समय पुलिस में नौकरी करने वाले ही इसे सबसे गन्दा काम कहते हैं।

ऊँच-नीच की बुनियाद ही शोषण पर, अपराध पर टिकी होती है। महीने में दो-तीन-चार लाख रुपयों के बराबर का प्रोडक्शन करने वाले मजदूर को हजार-दो हजार-चार हजार दिये जाते हैं। पुलिस नहीं हो तो यह लूट सम्भव नहीं है।

(बाकी पेज तीन पर)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद-121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच है)

रोलाटेनर्स लिमिटेड

रोलाटेनर्स लिमिटेड फैक्ट्री आज दुनियाँ में लाइन्ड कार्टन बनाने वाली नम्बर 1 फैक्ट्री है लेकिन मजदूर का खून चूसने में भी यह नम्बर 1 फैक्ट्री है। रोलाटेनर्स सन्डे हो या मन्डे, 24 घन्टे चलती है। इसमें 2 शिफ्ट ही कार्य करती हैं। यहाँ 8 घन्टे ड्युटी और 4 घन्टे ओवर टाइम होता है। यहाँ के मजदूर की मजबूरी है कि उसे 4 घन्टे ओवर टाइम करना पड़ता है क्योंकि यहाँ तनख्वाह ही इतनी कम है। यह फैक्ट्री ओवर टाइम भी बेसिक-डी.ए. पर डबल देती है पर आश्चर्य की बात देखिये : इसका बेसिक 175 रुपये मात्र है। हरियाणा सरकार का ग्रेड तो है परन्तु बेसिक बिलकुल निर्धारित नहीं है। मजदूर करे भी तो क्या ? चुपचाप खून के आँसू पीता है क्योंकि उसकी ना तो सरकार है, ना यूनियन और ना ही कोई पेपर। मजदूर समाचार में कभी किसी समस्या का समाधान आया नहीं।

26.9.96-- रोलाटेनर्स फैक्ट्री का एक मजदूर

ग़ज़ल

आसमाँ को छूती हुई कोठियाँ नहीं होतीं,
गर शहर के सीने पर झुग्गियाँ नहीं होतीं।

कांच का ये घर कबका टूट ही गया होता,
गर जो उसमें तैरती हुई मछलियाँ नहीं होतीं।

संविधान देश का अगर गाँव ने पढ़ा होता,
बूढ़ी माँ के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं होतीं।

देश खुद के पाँवों पर अब तलक खड़ा होता,
गर हमारी संसद में कुर्सियाँ नहीं होतीं।

आदमी के जिस्मों में भेड़िये न होते अगर,
औरतों के जिस्मों की मंडियाँ नहीं होतीं।

काश कि नहीं होते नेता कोई भारत में,
काश ये पुलिस वाली वर्दियाँ नहीं होतीं।

हाथ लोग बागों के बन्दूकें उठा लेते,
घर में जो बड़ी होती बेटियाँ नहीं होतीं।

— सुरेन्द्र चतुर्वेदी, अजमेर

20 सितम्बर को हरियाणा के लेबर मिनिस्टर और लेबर कमिश्नर फरीदाबाद आये। सर्किट हाउस में मीटिंग में उन्होंने माना कि फैक्ट्रियों में मैनेजमेन्टें बड़े पैमाने पर मजदूरों के नाम तक नहीं लिखती। इस बारे में कुछ तो करने की कहने पर दोनों ने चुप्पी साध ली।

लेबर मिनिस्टर से जब यह कहा गया कि अदालतें मजदूरों के पक्ष में कोई फैसला दे भी देती हैं तो उन फैसलों को बरसों तक लागू नहीं किया जाता, तब मन्त्री ने मात्र यह कहा, "हाँ ऐसा है पर ऐसा होना नहीं चाहिये।"

एक वर्कशॉप वरकर के दो खत

मजदूर समाचार पत्र सिर्फ कुछ ही जगहों पर आखिर क्यों ?

मजदूर समाचार पत्र जो कि फरीदाबाद शहर में मजदूरों के लिये डूबते को तिनके का सहारा है, फरीदाबाद में सही रूप से अपना विस्तार नहीं कर पा रहा है। इस समाचार पत्र के हॉकर जो कि तकरीबन हर कालोनी, हर सैक्टर में कम से कम एक या दो तो होने ही चाहियें थे, नहीं हैं। सिर्फ कुछ ही जगहों पर दिखायी देते हैं। जब फरीदाबाद, जिसमें कि 80 प्रतिशत सिर्फ मजदूर ही हैं, उसमें मजदूर समाचार को जानने वाले कुछ ही लोग होंगे तो उस शहर के मजदूरों का और मजदूर समाचार पत्र का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और, सबसे खास बात यह है कि ये समाचार पत्र सिर्फ फरीदाबाद की लिमिटेड फैक्ट्रियों तक ही सीमित है। जो वर्कशॉप और छोटी फैक्ट्रियाँ हैं उनको न तो ये समाचार पत्र जानता है और ना ही वो लोग इस समाचार पत्र को जानते हैं।

एक चिट्ठी उद्योगपतियों के नाम

फरीदाबाद शहर का मजदूर, जो कि पूरे महीने 12-12 घन्टे बिना नागा काम करता है, तनख्वाह के वक्त – जो कि उसे 40 से ले के 50 दिन के बाद पेमेन्ट की जाती है – गालियाँ सुनता, खुद की किस्मत को कोसता कोल्हू के बैल की तरह काम करता रहता है। और, अगर वो परेशान हो के नौकरी छोड़ देता है तो उसको महीनों चक्कर लगवा-लगवा के पैसे दिये जाते हैं – मजदूर कुछ कहे ना इसके लिये वर्कशॉप मालिक 3-4 गुन्डा टाइप दोस्तों को साथ बिठा लेते हैं। आज फरीदाबाद में लगभग 80 से ले के 90 प्रतिशत वर्कशॉपों का यही हाल है। सिर्फ कुछ ही मालिक ऐसे हैं जो कि समय पर तनख्वाह देते हैं अन्यथा जब मर्जी आती है किसी भी वरकर को रख लेते और निकाल देते हैं। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि साथी वरकर भी मालिकों की हाँ मे हाँ मिलाते हैं – वो ये नहीं सोचते कि कल को उनके साथ भी यही होना है।

हरियाणा सरकार तो सोई हुई है – बाऊ जी (बंसी लाल) से जो उम्मीदें यहाँ के वरकरों ने लगाई थी वो तो पता नहीं कब की दफन हो चुकी हैं। आज अगर फरीदाबाद, जो कि एक ओद्योगिक शहर है, अपनी बरबादी की तरफ़ बढ रहा है तो उसके लिये सिर्फ और सिर्फ ये उद्योगपति, राजनेता और सरकारी अधिकारी ज़िम्मेदार हैं। जब एक मजदूर को इतना मजबूर कर दिया जायेगा कि वो मेहनत करने के बाद भी भूखों मरे तो क्या करेगा वो ? खुद सोचिये, जवाब मिल जायेगा। ये समस्या सिर्फ मजदूरों की ही नहीं है बल्कि उन उद्योगपतियों की भी है जो फरीदाबाद में 1 या 2-4 मशीनें लगा के खुद को बाबूजी कहलवाना पसन्द करते हैं। लिहाजा ये बात ध्यान में रखी जाये – "जियो और जीने दो"।

19.9.96 — एक वर्कशॉप वरकर

एवरी हड़ताल (पेज चार का शेष)

एवरी में एक वरकर पर तीन मैनेजर हैं। फरीदाबाद स्थित प्लान्टों में 160 परमानेन्ट मजदूरों के साथ 500 मैनेजर हैं ! कई मैनेजर मजदूरों के साथ प्रोडक्शन का काम करते हैं। यह अजूबा दरअसल कुशल मजदूरों पर मैनेजर के लेबल चिपका कर उनके मजदूर होने के बारे में भ्रम पैदा करने की मैनेजमेन्ट की चाल है। ऐसे ही **हितकारी पोट्रीज** मैनेजमेन्ट ने मेन्टेनैन्स वरकरों को स्टाफ में बता कर और **आयशर ट्रैक्टर** मैनेजमेन्ट ने प्रोडक्शन करते डिप्लोमा वालों को स्टाफ करार दे कर जो असल में मजदूर हैं, मजदूर बन चुके हैं उन्हें मजदूरों से अलग व खिलाफ करने की साजिश की है। लेबलों के संग-संग मजदूरों में वेतन-भेद, अलग-अलग एग्रीमेन्ट आदि भी मैनेजमेन्टों की ऐसी चालबाजी के अंग हैं। एवरी मैनेजमेन्ट ने "मैनेजर" वरकरों से एग्रीमेन्ट कर ली है पर "वरकर" मजदूरों से समझौता करने में टाल-मटोल करती रही है।

एवरी इंडिया में यह अनिश्चितकालीन हड़ताल एग्रीमेन्ट के लिये है। 27 सितम्बर को मैनेजमेन्ट ने टोटल खर्चा दे कर फरीदाबाद के लीडरों को समझौते के लिये कलकत्ता भेजा है।■

बाटा

मजदूरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही बाटा मैनेजमेन्ट ने 19 सितम्बर को शिफ्ट खत्म होने के समय एक गुट के प्रमुख लीडर को सस्पैन्ड कर दिया। 20 को सुबह सस्पैन्ड लीडर के गुट ने मुखर विरोध किया और बाटा मजदूरों का मैनेजमेन्ट के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। विरोधी गुट की फैक्ट्री चलाने की कोशिशें फेल करते हुये बाटा मजदूरों ने चक्का जाम रखा। तीन घन्टे प्रोडक्शन बन्द रहने पर मैनेजमेन्ट झुकी। सस्पैन्शन वापस लेने पर ही फैक्ट्री चली।

बाटा में ही 26 सितम्बर को एक सोल कटर के खिलाफ एक्शन के लिये मैनेजमेन्ट में लिखा-पढत हुई। इस पर सब सोल कटरों ने आपस में चर्चा करके फैसला किया कि अपने साथी वरकर के खिलाफ मैनेजमेन्ट के एक्शन को रोकने के लिये 27 को सुबह ड्युटी आरम्भ होने पर काम बन्द रखेंगे। 27 को सोल कटरों द्वारा काम शुरू नहीं करने पर सब आटोमैटिक लाइनें बन्द होने की नौबत आई देख कर बाटा मैनेजमेन्ट पीछे हटी और एक्शन की बात रफा-दफा कर दी।■

हम चाहते हैं (पेज एक का शेष)

बराबरी वाली समाज व्यवस्था में शोषण नहीं होगा इसलिये दमन की जरूरत ही नहीं होगी। बड़े अपराधों के लिये आधार ही नहीं होता और छोटे-मोटे मामलों को लोग आपस में मिल-बैठ कर आसानी से निपटा सकते हैं। इसलिये बराबरी वाले समाज में पुलिस नहीं होगी।

● **जेलें खत्म करना** ताकि ऊँच-नीच की व्यवस्था बनाये रखने के लिये हम में से जिन्हें खतरनाक या नुकसानदायक करार दे कर सबक सिखाने के लिये पिंजड़ों में बन्द कर दिया जाता है वे आजाद हो सकें। यूँ तो अब पूरी दुनियाँ ही कैदखाने में बदल दी गई है पर फिर भी जेलों वाली कैद वहाँ बन्द लोगों को जिन्दा दफना कर तोड़ने और जेलों से बाहर लोगों में डर बैठाने का एक प्रमुख जरिया है। सुधारगृह कहे जाने वाले यह यातना स्थल इन्सानों को ऊँच-नीच के साँचे में ढालने के अत्यन्त क्रूर तरीके हैं। कैदियों से रुपये-पैसे वसूलने के लिये अथवा अपनी भड़ास निकालने या फिर अपने अस्तित्व का बोध कराने के लिये जेलरों-वार्डनों-जेल गार्डों की कैदियों के प्रति क्रूरता पुलिस को भी मात करती है।

बराबरी वाले समाज में किसी को भी कैद करने की जरूरत नहीं होगी। किसी कारणवश हम में से इस या उस को सहायता की आवश्यकता अवश्य पड़ सकती है और एक-दूसरे की मदद करना बराबरी वाले समाज की बुनियाद है।

● **अदालतें खत्म करना** ताकि जजों को गौण-तुच्छ बातों की गूढ-गम्भीर विवेचना से मुक्ति मिले और वकील दिन-भर झूठ बोलने की मजबूरी से आजाद हो सकें। कोर्ट-कचहरी न्याय के ढोंग-स्थल हैं जहाँ बाल की खाल निकालने की दीर्घ-लम्बी व खर्चीली प्रक्रिया द्वारा हमें थकाया जाता है। न्याय अन्धा नहीं होता बल्कि काणा होता है – इसकी आँख ऊँच-नीच की व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कसरत करती रहती है।

बराबरी वाली समाज व्यवस्था में अदालतें नहीं होंगी क्योंकि किसी पर मुकदमा चलाने की जरूरत ही नहीं होगी। समस्याओं का मिल-बैठ कर समाधान करना बराबरी की व्यवस्था की धुरी होगी।

● **प्रतिनिधियों-नुमाइन्दों-लीडरों-बिचौलियों को खत्म करना** ताकि हमारे सोचने, समझने, विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने पर लगी बेड़ियों से हम आजाद हो सकें। ऊँच-नीच की व्यवस्था में कदम उठाना, यानि करना तो हमें ही पड़ता है परन्तु क्या करना है- क्यों करना है - कैसे करना है को हमारे दायरे से बाहर निकाल कर प्रतिनिधियों के अखाड़े की चीजें बना दिया जाता है। बिचौलिया संस्कृति ऊँच-नीच को बनाये रखने की संस्कृति है।

आपस में विचार-विमर्श करना और मिल-जुल कर निर्णय लेना, कदम उठाने की ही तरह, बराबरी वाली समाज व्यवस्था में हमारे अपने दायरे में होंगे। सोचने-समझने-निर्णय लेने व कदम उठाने में लोगों की बराबरी की शिरकत बराबरी की बुनियादी शर्त है।

● **मैनेजमेन्टें खत्म करना** ताकि हमारे तन व मन को बीमार करने के संग-संग पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व तक के लिये खतरा बने उत्पादन व उत्पादन-प्रक्रिया को समाप्त कर सकें। ऊँच-नीच वाली वर्तमान व्यवस्था की धुरी मंडी-मार्केट है इसलिये पर्यावरण-पर्यावरण-पर्यावरण मात्र जाप है। मैनेजमेन्टें मार्केट साइन्स व मन्डी तकनीक की औलादें हैं इसलिये मानव व जीव विनाश वाले प्रोडक्शन को वैज्ञानिक पद्धति से करती हैं। तांडव जारी रखने में मैनेजमेन्टें अपने बन्धुओं, साइन्स व इंजिनियरिंग का भरपूर सहयोग ले रही हैं।

मंडी की आवश्यकताओं की बजाय बराबरी वाली समाज व्यवस्था में मनुष्यों की जरूरतों के अनुसार प्रोडक्शन होगा। क्या उत्पादन करना है, कितना पैदा करना है और प्रोडक्शन किस ढँग से करना है – इन पर लोग मिल-जुल कर विचार-विमर्श कर निर्णय करेंगे। निर्णय की धुरी इन्सानों की जरूरतें होंगी – और मानवों की आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू, एक अनिवार्य अंग स्वस्थ पर्यावरण भी है।

● **मुस्कानें बेचना खत्म करना** ताकि इस-उस माल की बिक्री के वास्ते मन मार कर तन को मार्केट के इशारों पर नचाने की कलाबाजी से छुट्टी मिले। मन की कुंठा के संग तन की चुस्ती से तौबा...

● **स्कूलों को खत्म करना** ताकि अध्यापकों और बच्चों को इन यातनागृहों से छुट्टी मिले। स्कूलों के लिये बच्चे वह कच्चा माल हैं जिसे मन्डी में बिक्री के लिये तैयार करने के वास्ते अध्यापक मशीन आपरेटरों के तौर पर रखे जाते हैं। ऊँच-नीच की सीढी के ऊपर वाले अथवा नीचे वाले डन्कों-डन्डों के माफिक बच्चों को ढालने के लिये मँहगे अथवा सस्ते स्कूल साँचे-डाइयाँ हैं.......

● **चूल्हे-चौके की चाकरी के संग-संग दिहाड़ी की गुलामी खत्म करना** ताकि महिलाओं को पारिवारिक गुलामी के साथ-साथ वेतन वाली दासता से मुक्ति मिले। ऊँच-नीच वाली व्यवस्था में यह दासता या वह गुलामी अथवा दोनों ही बेड़ियाँ औरतों के सम्मुख उपलब्ध विकल्प हैं....

● **मन्डी व मुद्रा को खत्म करना** ताकि झूठ - फरेब - तिकड़मबाजी - धोखाधड़ी के आज प्रमुख अखाड़े में सब को रगड़ा जाना बन्द हो.......

● **खुफिया-गोपनीय को खत्म करना** ताकि खुलापन महक सके......

● ....

हम जो चाहते हैं उन्हें हासिल करना मुश्किल नहीं है। वर्तमान में जो कुछ है उससे हम में से अधिकतर लोग बहुत-ही परेशान हैं। जो है उसे नकारना आम बात होती जा रही है। इसलिये वर्तमान ऊँच-नीच वाली व्यवस्था के अस्त्रों-शस्त्रों को खत्म करना मुश्किल नहीं है। दिक्कत के तौर पर विकल्प का प्रश्न मुँह बाये खड़ा लगता है। परन्तु हमारे विचार से यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपस में विचार-विमर्श कर हम आसानी से विकल्प का खाका बना सकते हैं और मिल-जुल कर उसे मूर्तरूप दे सकते हैं। हमारे साँझेपन, हमारी सामुहिकता में वर्तमान की क्रूरता-बर्बरता-झूठ-फरेब का विकल्प साकार करने की सहज क्षमता है।

हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिये हमें जिन तीर-तलवारों से निपटना है वे हम से बाहर ही नहीं हैं बल्कि हमारे अन्दर भी शिक्षा-दीक्षा ने छिपा कर पैठा रखे हैं। तभी तो हम "मेरी" व "तेरी" कमजोरी तो पहचानते हैं परन्तु "हमारी" ताकत नहीं जानते। ऊँच-नीच के किलों को मटियामेट करने के लिये हमें अपने व दूसरे के "मैं" की कमजोरी के संग-संग अपने साँझेपन, अपनी सामुहिकता के महत्व को समझने की जरूरत है। मिलजुल कर उठाये जाते अपने कदमों के महत्व को पहचानने की जरूरत तो है ही, अपने छोटे-से-छोटे साँझे कदमों के अनुभवों को आपस में बाँटने की आवश्यकता भी है। हमारे छोटे-बड़े सामुहिक कदमों की श्रृंखलायें विश्व-स्तर का ताना-बाना बुन कर मनुष्यों के बीच एक नई बराबरी वाली समाज व्यवस्था को साकार कर देंगी। तथास्तु। इति नई सीरीज का 100 वाँ अंक। ■

इस अंक की हम पाँच हजार प्रतियाँ ही फ्री बाँट पा रहे हैं। पाँच हजार मजदूर अगर हर महीने एक–एक रुपया दें तो दस हजार प्रतियाँ फ्री बँट सकेंगी।

झालानी टूल्स में नई नौटंकी

मजदूरों का मार्च माह का वेतन भी सितम्बर अन्त तक नहीं दिया गया है। छह महीनों के वेतन नहीं दिये जाने पर मजदूरों के बढते गुस्से को दलदल में डालने के लिये मैनेजमेन्ट और लीडरों ने फिर नौटंकी शुरू कर दी है।

अपनी परेशानियाँ दूर करने के लिये झालानी टूल्स के वरकर लीडर बदलते आये हैं और हर बार तवे से चूल्हे में गिरने जैसा रिजल्ट रहा है। तनखा में कटौती, अन्य बकाया के संग-संग तीन महीनों का वेतन नहीं दिया गया तब मई में एक पुराने गिरोह की नई डुगडुगी पर मजदूरों ने फिर आस लगाई। लीडर बदले.....और छह महीनों की तनखा बकाया हो गई!

मैनेजमेन्ट नोटिस लगा रही है कि नये लीडरों ने 200 टन हैन्ड टूल्स प्रतिमाह का प्रोडक्शन करने पर वेतन दिये जाने की 3 जून को एग्रीमेन्ट की है। मैनेजमेन्ट कहती है कि समझौते के अनुसार उत्पादन होने पर ही तनखा देगी। दो महीनों में भी 200 टन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा ...... बिजली बोर्ड ने बकाया के भुगतान के लिये कनेक्शन काट दिये हैं और जनरेटरों को चलाने के लिये तेल नहीं है!

फूँ–फाँ करने को मजबूर लीडरों ने ड्रामा वाली तलवारबाजी करते हुये 7 सितम्बर से डिस्पैच रुकवा दिया। इस पर मैनेजमेन्ट ने एग्रीमेन्ट तोड़ने के नाम पर 1993 से हर्जाने के संग-संग अब प्रतिदिन के नुकसान का हिसाब लगा कर मजदूरों से इन्हें वसूल करने के नोटिस लगा दिये हैं....

वेतन नहीं दिये जाने पर होने वाली आर्थिक हानि, मानसिक कष्ट और सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट का हिसाब झालानी टूल्स के 2200 मजदूर और 300 स्टाफ के लोग कब लगायेंगे? मैनेजमेन्ट व लीडरों की जमात से इनका हर्जाना वरकर कब डिमान्ड करेंगे?

मैनेजमेन्ट को डेढ़ साल से ऊपर हो गया है हर मजदूर के वेतन में से दस रुपये प्रतिमाह काट कर लीडरों को देते। इसके एवज में इससे पहले वाली नौटंकी में मजदूरों की हाउसिंग की 22 एकड़ जमीन बेचने में एक करोड़ रुपये से ऊपर की हेरा-फेरी की गई। डिस्पैच रोकने वाली यह नौटंकी थर्ड प्लान्ट को बेचने में किये जाने वाले करोड़ों के गोलमाल पर परदा डालने की तिकड़म का एक हिस्सा लगती है।

ऊपर से, लीडर खुद केस नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेन्ट की है इसलिये मजदूर अपने-अपने नाम से केस करने के लिये एक लाख रुपये वकीलों को देने के लिये लीडरों को दें.........

झालानी टूल्स के मजदूरों और स्टाफ को अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि उनके बकाया वेतन, जमा नहीं किये गये प्रोविडेन्ट फन्ड, कई बरसों से वर्दी-जूते-साबुन-साफी-एल टी ए-बोनस के बकाया और **सर्विस-ग्रेच्युटी** के पैसे प्रति व्यक्ति एक लाख रुपये के आस-पास हैं। यह राशि 25 करोड़ रुपयों से ऊपर ही बैठेगी। कम्पनी की इस देनदारी के संग-संग कम्पनी पर बैंकों के भारी कर्ज, ई एस आई-बिजली बोर्ड आदि-आदि के बकाया भी हैं। **लाला-लूला कोई मालिक नहीं है और सब देनदारियों की जिम्मेदार कम्पनी है, यानि कम्पनी के बही-खातों में दर्शाई कम्पनी की सम्पति से भुगतान होना है।** ऐसे में थर्ड प्लान्ट बेचने देना....

इसलिये नौटंकियों से मजदूरों की समस्यायें हल नहीं होंगी बल्कि इनके जरिये तो मजदूरों को और दलदल में धकेला जाता है।

किसी महाबलि या महातिकड़मबाज की बजाय मजदूरों में वह ताकत है कि अपने पैसे वसूल सकते हैं। इसके लिये मजदूरों को आपस में विचार-विमर्श करने के साथ-साथ अन्य अनेकों से राय ले कर मिलजुल कर निर्णय लेने होंगे और साँझे-सामुहिक कदम उठाने होंगे। अन्य कोई राह न तो झालानी टूल्स के वरकरों के लिये है और न अन्य किन्ही मजदूरों के लिये। ■

ईस्ट इंडिया में तालाबन्दी

अगस्त में तीन बार लिस्टें टाँग कर 300 मजदूरों की मजे से छँटनी करने के बाद 2 सितम्बर को टेबल प्रिन्टिंग में घाटा बता कर ईस्ट इंडिया कॉटन मिल मैनेजमेन्ट ने अजन्ता प्रिन्टिंग खाते को बन्द करने का नोटिस गेट पर चिपकाया और अजन्ता के 600 मजदूरों को आदेशानुसार फैक्ट्री में इस या उस जगह झख मारने को कहा। कोई भी बता सकता है कि इससे मजदूरों में असन्तोष बढेगा। मैनेजमेन्ट ने 8 व 9 सितम्बर को अगस्त के वेतन की पर्चियाँ बाँटी पर 10 को भी तनखा दी नहीं। छँटनी के बारे में मौन और एग्रीमेन्ट के लिये भागमभाग लोगों ने ऐसे में 11 सितम्बर को टूल डाउन का फतवा दिया और 12 को मैनेजमेन्ट ने ईस्ट इंडिया ग्रुप के इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित प्रिन्टिंग व प्रोसेसिंग प्लान्ट और 24 सैक्टर स्थित पावरलूम सैक्शन में तालाबन्दी कर दी। दोपहर ढाई बजे वाली शिफ्ट के वरकरों को पुलिस ने गेटों पर रोक दिया और सुबह साढे छह वाली तथा जनरल शिफ्ट के वरकर आहिस्ता-आहिस्ता रात दस बजे तक फैक्ट्रियों से बाहर निकल गये। हर जगह मैनेजमेन्टें छुट्टी के दिन तालाबन्दी करती हैं क्योंकि फैक्ट्री से मजदूरों को निकालना लोहे के चने चबाना होता है — लॉक आउट पर फैक्ट्री में घुसना अभी तक यहाँ मजदूर कानून-वानून में उलझे होने की वजह से कम ही करते हैं। परन्तु ईस्ट इंडिया मैनेजमेन्ट द्वारा मजदूरों की पूरी शिफ्टें अन्दर होने के वक्त तालाबन्दी करने से लगता है कि किन्ही कारणों से उसे भरोसा था कि फैक्ट्री आसानी से खाली हो जायेगी। अगस्त की तनखा नहीं दी गई है इसलिये मैनेजमेन्ट द्वारा 12 सितम्बर को की गई तालाबन्दी मजदूरों के लिये असल में 10 अगस्त से की गई तालाबन्दी है।

12 सितम्बर को तालाबन्दी के बाद से 30 सितम्बर तक पावरलूम और प्रिन्टिंग व प्रोसेसिंग के 3000 मजदूरों ने इकट्ठे बैठ कर आपस में एक बार भी विचार-विमर्श नहीं किया जबकि उन द्वारा हर रोज यह करना बनता है — इस बीच बस दो बार लीडरों के भाषण हुये हैं। 12 सितम्बर से हर रोज सुबह व शाम जलूस निकालना बनता था परन्तु 30 सितम्बर तक एक भी जलूस ईस्ट इंडिया मजदूरों ने नहीं निकाला। यानि, **मजदूरों द्वारा अपनी ताकत बढाने के लिये कदम नहीं उठाये गये। इसका कारण क्या है? लीडर बहुत बिजी हैं और लीडरों के कहे बिना वरकर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि गड़बड़ हो सकती है! लीडर बहुत-बहुत भागदौड़ कर रहे हैं पर क्या करें पुलिस-प्रशासन में सब बिके पड़े हैं !!**

ईस्ट इंडिया मजदूरों ने इसी प्रकार अपने विवेक को गिरवी रखा, अपनी नकेल कुछ लोगों को सौंपे रखी तो मैनेजमेन्ट अपनी शर्ते मजदूरों पर थोप देगी। गेटों के बाहर कर दिये गये तीन हजार मजदूर तमाशबीन नहीं हैं कि कहें, "देखो क्या होता है"। तीन हजार मजदूर तिनका भी नहीं हैं कि कोई उन्हें चबा जाये। ईस्ट इंडिया ग्रुप के मजदूर रोज इकट्ठे हो कर आपस में विचार–विमर्श करेंगे तो मजदूरों की ताकत बढेगी। सब वरकर मिलजुल कर निर्णय लेंगे और रोज सुबह व शाम जलूस निकालने जैसे अपनी ताकत बढाने वाले कदम उठायेंगे तो मैनेजमेन्ट को झुकना पड़ेगा।

इस महारथी के कहने पर उठना-बैठना या फिर एक भीम से मोहभंग होने पर दूसरे अफलातून के चक्कर में पड़ना मजदूरों के लिये दलदल में धँसने की राह है। ■

एवरी इंडिया में हड़ताल

23 सितंबर से एवरी इंडिया के कलकत्ता व फरीदाबाद स्थित सभी प्लान्टों में हड़ताल है। 23 को हड़ताल शुरू होने पर सैक्टर–25 स्थित एवरी के तीन प्लान्टों के 160 मजदूरों को पुलिस पकड़ कर बल्लबगढ़ थाने ले गई और ढाई घन्टे वरकरों को वहाँ बैठा कर रखा। 24 सितम्बर को पुलिस फैक्ट्री के गेटों से झन्डे उतार कर ले गई। 29 सितम्बर को जब हम एवरी वरकरों से मिले तब तक हड़ताल जारी थी और मजदूरों में पुलिस व मैनेजमेन्ट के प्रति भारी गुस्सा था।

(बाकी पेज दो पर)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० ऑफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।